भूमि की वजह से नहीं लटकेंगी निवेश की योजनाएं

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT
10-12 FEBRUARY, 2023

राजीव बाजपेयी • लखनऊ

- प्रशासन का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पूर्व इंडस्ट्री पर अधिक फोकस
- लैंड बैंक के लिए विशेष सेल बनेगी और तैनात होंगे नोडल अधिकारी

लखनऊ में निवेश के प्रस्ताव अगर उपयुक्त जमीन न मिलने की वजह से अटके हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने खास योजना तैयार की है। प्रशासन अब उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके लिए सेल का गठन होगा, जो लैंड बैंक की जानकारियां उद्यमियों को उपलब्ध कराएगा। जमीनें न मिलने की वजह से निवेश के कई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दूसरों जिलों में संभावनाएं तलाश रहे हैं।

फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से राजधानी में ही दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इनमें से अब करीब 29 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हो चुका है, लेकिन शेष अभी किसी ने किसी वजह से पाइप लाइन में ही हैं। कुछ ही समय बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रस्तावित है जिसमें फाइनल हो चुके निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार का कहना है कि इस वर्ष सबसे अधिक फोकस इंडस्ट्री पर रहेगा। निवेश की छोटी बड़ी सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए उद्यमियों और निवेशकों को जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका निदान त्वरित गति से किया जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट जमीन नहीं मिलने की वजह से देरी में हैं उनके लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जाएगी। जिला पंचायत क्षेत्र के करीब 400 गांवों में जो भी उपयुक्त जमीन हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि निवेशकों की सुविधा हेतु मास्टर प्लान के अंतर्गत ऐसी भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपलब्ध हैं, उसकी सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे जमीन खरीदने में आसानी रहे। जमीन खरीदवाने से लेकर उसे सभी तरह की अनापत्ति दिलाने में भी प्रशासन सहयोग करेगा। इसके लिए पहले से ही नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष विकास खन्ना का कहना है कि उद्यमों के लिए उपयुक्त और उचित मूल्य पर जमीन खोजना सबसे मुश्किल है। जमीन महंगी होने की वजह से प्रोजेक्ट कास्ट पर असर पड़ता है, जिससे निवेश के प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए निवेशकों को बजट के भीतर और कनेक्टिवटी वाली सड़कों के आसपास जमीनें उपलब्ध कराएं।

विभागवार निवेश प्रस्ताव (करोड़ में)

विभाग	प्रस्ताव	निवेश
सौर ऊर्जा	15	63060
हाउसिंग	167	39269
शहरी विकास विभाग	27	17502
यूपीसीडा	35	13999
यूपीईआइडीए	11	11720
पर्यटन	66	7998
ऊर्जा	01	7800
चिकित्सा स्वास्थ्य	22	6440
खाद्य सुरक्षा	18	5946
एमएमएमई	201	4557
पशुपालन	35	328.74
आइटी इलेक्ट्रानिक्स	25	4417
डेयरी	24	618

जीबीसी के लिए तैयार योजनाएं

टाटा टेक्नोलाजी	4174 करोड़
ओमेक्स इंफ्रा	एक हजार करोड़
हमसफर प्रालि	800 करोड़
अपोलो अस्पताल	700 करोड़
बालाजी बेफर्स प्रालि	500 करोड़
रिशिता डवलपर्स	812 करोड़
बीबीडी ग्रुप	600 करोड़
इकाना ग्रुप	344 करोड़
ओरो रियल इंफ्रा	105 करोड़
जीके अथारिटी	200 करोड़
ओरो इंफ्रा डेवलपर्स	439 करोड़
एक्सीलिया ग्रुप	100 करोड़